उत्तराखण्ड शासन

देवभूमि रजत उत्सव
9 नवंबर 2024-25 | उत्तराखण्ड

जन-जन की सरकार
4 साल बेमिसाल
उत्तरोत्तर विकास पथ पर अग्रसर
उत्तराखण्ड

“ 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखण्ड इन दोनों ही स्तंभों को लगातार मजबूत कर रहा है। ये दशक उत्तराखण्ड का दशक है। ”

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

“ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड सर्वांगीण विकास की नई मिसाल बन रहा है। स्थानीय उत्पाद, बेहतर कनेक्टिविटी, उद्योग एवं निवेश तथा हर मौसम पर्यटन सहित देवभूमि अपनी अलौकिक विरासत को संजोते हुए विकास के नए आयाम छू रही है। ”

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

विकसित भारत सशक्त उत्तराखण्ड

विरासत भी, विकास भी

इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कनेक्टिविटी

- केदारनाथ–हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना
- दिल्ली–देहरादून एलिवेटेड रोड निर्माण
- ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रगति पर
- टनकपुर–बागेश्वर रेल सर्वे स्वीकृत
- सौंग व जमरानी बांध परियोजना
- पर्वतीय जिलों में हेली सेवा विस्तार

अर्थव्यवस्था, निवेश एवं उद्योग

- ₹3.56 लाख करोड़ निवेश समझौते
- ₹1 लाख करोड़+ ग्राउंडिंग
- अर्थव्यवस्था 26 गुना वृद्धि
- ₹1.11 लाख करोड़+ वार्षिक बजट
- खुरपिया में स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप
- हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड

हरित ऊर्जा एवं ग्रामीण विकास

- 1 गीगावाट+ सौर ऊर्जा क्षमता
- 42,000+ सोलर रूफटॉप
- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (सीमांत गांव विकास)
- महक क्रांति व मिलेट्स मिशन

संस्कृति एवं विरासत का संरक्षण

- केदारनाथ–बदरीनाथ मास्टर प्लान
- मानसखण्ड मंदिर माला मिशन
- शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ
- संस्कृत ग्राम पहल
- गीता अध्ययन पाठ्यक्रम में शामिल
- दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र
- स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन (गढ़वाल–कुमाऊं)

सुशासन

- ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान
- 30,000+ युवाओं को सरकारी नौकरी
- 950+ सेवाएं ऑनलाइन (अपुणि सरकार पोर्टल)
- 12,000 एकड़ अतिक्रमण मुक्त
- पेंशन योजनाओं में वृद्धि एवं मासिक भुगतान

बड़े निर्णय

- समान नागरिक संहिता
- सशक्त भू-कानून
- सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून
- नकल विरोधी कानून
- अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण

संकल्प से शिखर तक

नेशनल लेवल रैंकिंग व प्रोत्साहन

- निर्यात तैयारी सूचकांक में प्रथम (छोटे राज्य)
- एसडीजी इंडेक्स में शीर्ष स्थान
- स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर’
- खनन सुधारों में देश में दूसरा स्थान
- शहरी सुधारों हेतु ₹264.5 करोड़ प्रोत्साहन

30 से अधिक नीतियां

नीतिगत सुधार

- औद्योगिक नीति, पर्यटन एवं योग नीति
- नई फिल्म नीति (50% तक सब्सिडी)
- मिलेट्स नीति, कीवी नीति (70% अनुदान)
- ड्रैगन फ्रूट प्रोत्साहन योजना
- महक क्रांति 2026-36
- महिला स्वरोजगार एवं लखपति दीदी योजना आदि

प्रधानमंत्री जी के नौ आग्रह

स्थानीय लोगों से: बोली-भाषा का संरक्षण, एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छ जल, गांव से जुड़ाव, तिबारी वाले घरों को संवारें

पर्यटकों से: प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें, वोकल फॉर लोकल, यातायात के नियम अपनाएं, तीर्थों की मर्यादा का पालन करें।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी

www.uttarainformation.gov.in | DIPR_UK | UttarakhandDIPR | UttarakhandDIPR